जन गर्जन

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के आह्वान पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वीर सिपाही और भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 113वीं जयंती 'देश प्रेम दिवस' के रूप में देशभर में मनाया गया। नेताजी के नाम पर देश प्रेम दिवस मनाने की सार्थकता को लेकर देशभर में फारवर्ड ब्लॉक ने मांग भी उठाई थी, जिसके लिये प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को प्रति वर्ष करोड़ों की संख्या में पोस्टकार्ड भी भेजे गये, पर सरकारी स्तर पर इसे स्वीकार नहीं किया गया। देश के प्रति सुभाष बोस कितने समर्पित थे यह आजादी की लड़ाई के दौरान उनके संघर्षों से तो उजागर होता ही है।

नेताजी के इस अपूर्व योगदान को याद करने के लिये अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने उनके जन्मदिन 23 जनवरी को 'देश प्रेम दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसकी शुरूआत कई साल पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा भी देश के विभिन्न हिस्सों में नेताजी का जन्मदिन विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से मनाया गया।

ऐतिहासिक महानिष्क्रमण के गवाह गोमोह रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गोमोह जंक्शन

झारखण्ड : नेताजी की 113वीं जयंती पर इस साल सबसे उल्लेखनीय कार्यक्रम झारखण्ड के गोमोह में हुआ। सुभाष बोस के प्रशंसकों, समर्थकों और अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की वर्षों से मांग थी कि गोमोह स्टेशन का नामकरण नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर किया जाये। फारवर्ड ब्लॉक इसके लिये लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा था। इस बार माननीय रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने गोमोह स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गोमोह जंक्शन करने की घोषणा की।

इस संबंध में 23 जनवरी को गोमोह स्टेशन पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोमोह रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि माननीय रेलमंत्री ने नामकरण समारोह का उद्घाटन किया। जनसभा समारोह में साथी देवब्रत बिश्वास, राष्ट्रीय महासचिव अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, टेकलाल महतो सांसद, मथुरा प्रसाद महतो, विधायक, अपर्णा सेनगुप्ता पूर्व मंत्री झारखण्ड सरकार सह प्रांतीय अध्यक्ष अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक झारखण्ड, जनार्दन पाण्डेय, प्रांतीय महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक झारखण्ड, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, गिरिनाथ सिंह, विधायक, गौतम सागर, पूर्व विधायक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

ज्ञात हो कि 18 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसी गोमो रेलवे स्टेशन से भेष बदलकर देश छोड़कर विदेश चले गये थे तथा आजाद हिन्द फौज एवं अस्थायी आजाद हिन्द सरकार गठन कर अमेरिका एवं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ समझौता विहीन संग्राम का संचालन किया था। गोमो रेलवे स्टेशन महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के "ऐतिहासिक महाभिनिष्क्रमण" का गवाह रहा है।

इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुये पार्टी महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास ने कहा कि रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर गोमो रेलवे स्टेशन का नामकरण कर देश के करोड़ों देशभक्त जनता की वर्षों से लंबित मांग की पूर्ति कर नेताजी सुभाष एवं स्वतंत्रता संग्राम के इस महान सपूत को महिमा मंडित किया है। उन्होंने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि नेताजी के नाम पर गोमोह में ऑडीटोरियम तथा यहाँ पर नेताजी सुभाष तथा स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लाईट एण्ड साउण्ड के माध्यम से आम जनता को दिखाये जाने का प्रबंध किया जाना चाहिये जिससे देश की राष्ट्र भक्त जनता खासकर युवाओं को देशभक्ति के गौरव पूर्ण इतिहास से परिचित कराया जा सके ताकि वे देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो सकें।

साथी बिश्वास ने कहा कि आज का इस "नामकरण" के समारोह के लिये देश की जनता फारवर्ड ब्लॉक एवं सामाजिक नागरिक संगठनों की लंबे संघर्ष की जीत है।

समारोह को संबोधित करते हुये रेल मंत्री लालू प्रसाद यादन ने कहा कि मेरे लिये यह सौभाग्य की बात है कि भारत के महान सपूत देश प्रेमियों में सर्वोत्तम देश प्रेमी भारत के करोड़ों युवाओं के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया के युवाओं के प्रेरणास्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर गोमोह रेलवे स्टेशन का नामकरण करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस महान देशभक्त का अभिनंदन करता हूँ।

इस अवसर पर अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की झारखण्ड राज्य कमिटी की ओर से एक विशाल रैली एवं जुलूस निकाला गया जिसमें साथी मोफिज शाहिल, साथी सानू चौधरी, साथी हंजला बिन हक, साथी गौतम सेनगुप्ता, साथी साथी सुनील वर्मन, साथी सलाउद्दीन, साथी प्रेमचन्द गुप्ता, साथी उत्तम गोस्वामी, साथी चांद उगानकी, साथी लखन आचार्य, साथी संतु गोस्वामी, आदि नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

उसके अलावा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती पर पार्टी की राँची जिला इकाई की ओर से राँची कचहरी चौक एवं राँची विश्वविद्यालय चौक पर जुलूस एवं सभा आयोजित की गयी जिसका नेतृत्व साथी सुमित बरियार एवं साथी उमाशंकर पाण्डेय ने किया। धनबाद, झरिया, बाघमारा, गोविन्दपुर, गढ़वा, डालटेन गंज, लातेहार, जामताड़ा, बोकारों, कोडरमा, हजारी बाग, डुमका जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष की 113वीं जयन्ती पर समारोह आयोजित कर धूमधाम से मनाया एवं नेताजी के सपनों का भारत के पुनर्निर्माण के लिये साम्राज्यवाद विरोधी समझौता विहीन संघर्ष को देश में तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बिहार में राज्यभर में देश प्रेम दिवस बड़ी धूम-धाम से मना।

पटना: अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के बिहार राज्य इकाई के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 113वीं जयन्ति देश प्रेम दिवस के रूप में विधायक क्लब सभागार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना में आयोजित की गयी। समारोह का शुभारंभ सेवानिवृत न्यायाधीश व वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद ने माल्यार्पण कर नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिये नेताजी के तरह हर कुर्बानियों के लिये आह्वान किया। बिहार के पूर्व कानून मंत्री वरीय अधिवक्ता, श्री शकील अहमद खॉ ने नेताजी के तेजस्वी सोच पर बल दिया। आगे सभा को वरीय अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, श्री इन्दूशेखर प्रसाद सिन्हा ने नेताजी के जन्म दिवस पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया। सभा को सम्बोधित करने वालों में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ० (श्रीमति) इन्दीवर, श्री प्रणव कुमार, श्री पी.पी. आर्या तथा एक जाने माने प्रोफेसर विमला कुमारी आर्य, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक बिहार राज्य कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष साथी राम पदारथ सिंह, महासचिव साथी आजाद, साथी दिनेश सिंह, साथी श्री नारायण सिंह, साथी मनोज कुमार सदस्य बिहार राज्य कमिटी एवं मजदूर नेता, साथी भूपेश कुमार गुप्ता (बमबम), साथी संतोष कुमार, साथी द्वारिका पासवान, साथी रविशंकर साव, साथी पी.एन. सिंह, साथी अजय सिंह, साथी परशुराम ठंठोरिया आदि ने संबोधित किया।

मुजफ्फरपुर : पार्टी की मुजफ्फरपुर जिला कमेटी द्वारा मैठी चौक पर जयन्ती समारोह 'देश प्रेम दिवस' के रूप में आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध किसान नेता साथी चन्द्रदेव सिंह ने किया तथा मंच का संचालन किसान सभा अध्यक्ष साथी राकेश कुमार सिंह ने किया।

सभा का प्रारम्भ पार्टी के झण्डारोहण कर अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रीय महामंत्री टी.यू.सी.सी. साथी एस.पी. तिवारी ने किया एवं नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया।

साथी तिवारी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि अँग्रेजों के गुलामियों में जकड़ी हुई थी तो सुभाष चन्द्र बोस ने अपनी डिग्री को फाड़कर के देश की आजादी के लिये भारतवासियों से खासकर कके युवाओं ने उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा। आज उन्हीं की कुर्बानियों तथा भगत सिंह, राजगुरू, सूखदेव खासकर इसी मुजफ्फरपुर की मिट्टी में जन्मा जुब्बा साहनी जैसे लोगों की कुर्बानी से समझौता भरी आजादी कांग्रेस ने ली, कांग्रेस पार्टी उस समय के सिपहसलार लोगों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एवं भारत की जनता के साथ धोखा दिया है जिसके कारण सम्प्रदायवाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है।

टी.यू.सी.सी. के प्रांतीय महामंत्री साथी वकील ठाकुर ने नेताजी द्वारा चलाया हुआ करेंसी का जिक्र किया तथा कहा कि उस करेंसी को 19 देशों ने मान्यता दिया था। ठाकुर जी ने कहा कि ठाकुर जी ने कहा कि सरकार मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करे तथा जनता के सामने प्रचारित करें।

ऑल इण्डिया स्टूडेन्ट्स ब्लॉक के राष्ट्रीय महामंत्री साथी अमरेश नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर बिहार सरकार एवं भारत सरकार से मांग की है कि मुजफ्फरपुर शहर का नाम जुब्बा साहनी नगर किया जाये, जारंग कॉलेज को मान्यता एवं मैठी से कोठिया तक की सड़क पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाये।

साथी राम दयाल राय, साथी हबीब अन्सारी, साथी जयनारायण राय, साथी वीणा देवी, साथी जयनन्दन सिंह, साथी सत्यनारायण चौधरी (सीपीआई नेता) ने भी नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया।

पाठ्यक्रम में शामिल हो नेताजी की कुर्बानियों का इतिहास

रोपड़ : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की देश की आजादी के लिये दी कुर्बानियों संबंधी इतिहास को स्कूलों तथा कॉलेजों के के सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिये ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी नेताजी को देशभक्ति के बारे जान सकें। यह बात पंजाब सरकार के शैक्षणिक सचिव एसएस ढिल्लों (आईएएस) ने नेताजी मॉडल स्कूल, रोपड़ में आयोजित देश प्रेम दिवस समारोह में कहीं। इस अवसर नेताजी के सपनों को भारत बनाओं विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा नेताजी के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगायी गयी थी। इसके अलावा नेताजी सुभाष फाउण्डेशन के सदस्य एवं अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के सचिव मण्डल के सदस्य साथी वी.पी. सैनी ने कहा कि जब तक हम अपने देश प्रेम की भावना को उजागर नहीं करेंगे तथा अपने अंदर कुर्बानी की भावना पैदा नहीं करेंगे तब तक हम नेताजी के सपनों का भारत नहीं बना पायेंगे। इस मौके पर नगरपालिका के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सत्यपाल, डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नरेश गौतम, गाँधी मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल बीपीएस ठाकुर, संतोख सिंह वालीया, प्रो. बी.एस. सत्या आदि मौजूद थे।

चंडीगढ़ : कभी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने नारा दिया था 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'। नेताजी ने देश को आजाद कराने के लिये स्वयं को न्यौछावर कर दिया लेकिन अब तो नेता होने के मायने ही बदल गये हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने जन्मदिवस पर चंडीगढ़ के सूद भवन में आयोजित कार्यक्रम में विद्वानों ने यही राय रखी। नेताजी सुभाष क्रान्ति मंच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में पंजाब के एडीजीपी चन्द्रशेखर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुये जबकि डॉ. सुनंदन सूद, पंजाब के आईएएस अधिकारी एसएस ढिल्लों विशेष अतिथि थे।

अमृतसर : अमृतसर के भण्डारी रेलपुल पर में नेताजी की मूर्ति के पास आजाद हिन्द फौज एसोसिएशन के सदस्यों ने जमायत होकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की शपथ ली। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आज देश जिस आर्थिक और राजनीतिक एवं समाजिक संकट से गुजर रहा है, उससे छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता नेताजी के मिशन का अनुकरण है।

इसके अलावा वक्ताओं ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथी बलदेव बक्शी ने इस अवसर पर देशभक्तों के चित्रों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

सिरसा : सिरसा के सी.एम. के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म जयंती के संबंध में इतिहास विभाग द्वारा एक समारोह किया गया जिसमें कॉलेज की प्रेसिडेंट डॉ. श्रीमती विजय तौमर ने देशभक्तों द्वारा की गयी कुर्बानियों को याद करते हुये कहा कि हमें शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिये और उनके दिखाये मार्ग चर चलना चाहिये।

इसके अलावा एस.एन. आर्य हाई स्कूल तपामंडी में भी एक समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रिंसीपल सुरिंदर शर्मा ने की।

मुक्तसर : मुक्तसर के देशभक्त डैंन्टल कॉलेज एवं अस्पताल में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मार्किट कमिटी के चेयरमैन हनी बराड़ फतनवाला, चोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य नवतेज सिंह कयोणी, कॉलेज प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरमेज सिंह अगरोया, सुपरवाईजर बागी मान एवं जन संपर्क अधिकारी श्री रामदन ने नेताजी और स्वतंत्रता सेनानी लाल सिंह के चित्रों पर फूल मालायें भेंट की।

मध्य प्रदेश में भोपाल सहित अनेक जगहों पर देश प्रेम दिवस श्रद्धा व सम्मान के साथ मना

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 113वीं जयंती शुक्रवार को राजधानी में देश प्रेम दिवस के रूप में मनायी गयी। इस अवसर पर अनेक संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित कर उनको याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प किया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राज्य इकाई सचिव सीताराम शर्मा की अध्यक्षता में अशोका गार्डन चौराहा स्थित सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित किया गया।

राज्य में भाजपा ने इस अवसर पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया। राष्ट्रीय धावक अनूप कुमार ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया।

इसके अलावा पिपरिया में सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया।

इटारसी के आयुध निर्माणी परिसर स्थित विन्ध्याचल क्लब में जयंती समारोह का आयोजन किया गया।

आजादी कोई थाली में सजाकर देने नहीं आयेगा अपना जन्मसिद्ध अधिकार छीनना होगा।

उन्नाव : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन 'देश प्रेम दिवस पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद के अध्यक्ष मकूर निवासी दादा रामस्वरूप यादव को 13 जनवरी 1939 की वह अलसुबह जा भी याद है जब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने यहाँ क्रान्तिकारियों को ललकारते हुये कहा था कि आजादी कोई थाली में सजाकर देने नहीं आयेगा। इसके लिये हमें खून बहाकर अपना जन्मसिद्ध अधिकार छीनना होगा।

स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जनपद के रणबांकुरों ने वीरोचित त्याग व बलिदान की अनुपम गाथा आज भी बना है यहाँ की धी ही कलम व तलवार की धन रही है। आजादी आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद ने जवानी मातृभूमि पर न्यौछावर कर दी तो राजा राम बक्श सिंह व राजा जसा सिंह ने स्वतंत्रता के प्रथम आंदोलन में जिस तरह फिरंगी सेना को मात दी उससे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के उद्घोषक नेता जी सुभाष चन्द्र बोस भी प्रभावित रहे। और शहीदे आजम आजाद की शहादत के बाद इसी जनपद के नाम मकूर में तीन दिन निवास कर फारवर्ड ब्लॉक का गठन किया।

फतेहपुर : आशा परिवार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयंती 'देश प्रेम दिवस के रूप में वृहद रूप से मनाया। कार्यक्रम में मैगसेसे पुरस्कार विजेता संदीप पाण्डेय एवं प्रांत गौरव विशंभर दयालु त्रिपाठी की पुत्रि रश्मि दीक्षित व प्रमुख शिक्षाविद धीरेन्द्र कुमार शुक्ल मुख्य रूप से उपस्थित थे।

कांग्रेस (आई) का घृणित षड्यन्त्र

नई दिल्ली : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी द्वारा स्थापित पार्टी अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी के 113वें जन्मदिवस को देशभर में 'देश प्रेम दिवस' के रूप में मनाया। दिल्ली में आई.टी.ओ. के नजदीक भगत सिंह पार्क से लेकर दरियागंज स्थित सुभाष पार्क तक एक रंगारंग रैली का आयोजन किया। जहाँ अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव श्री जी. देवराजन ने जनसभा को सम्बोधित किया।

श्री देवराजन ने जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस(आई) नीत संप्रग सरकार ने डी.ए.वी.पी. के जरिये नेताजी के जन्मदिवस से सम्बन्धित कोई विज्ञापन प्रिन्ट मिडिया या इलैक्ट्रिक मिडिया में न देकर नेताजी का निरादर किया है। जबकी एक छोटी पुलिया के बनने के बाद यही सरकार उसके उद्घाटन के लिये लाखों रूपये खर्च कर देती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस (आई) हमेशा से ही अपनी घृणात्मक षड्यन्त्रों से नेताजी के विचारों और उनके योगदान को दबाती रही है। उन्होंने मांग की कि नेताजी के जन्मदिवस को 'देश प्रेम दिवस' घोषित किया जाये और नेताजी के अंतर्ध्यान से जुड़ी मुखर्जी जाँच आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करो। उन्होंने आगे कहा कि आज का नौजवान राष्ट्र विरोधी जाल में फँसता जा रहा है, ऐसे में सरकार को नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिये नेताजी के इतिहास और जीवनवृत्त को पाठ्यक्रमों में शामिल कर एक विशेष कार्यक्रम तैयार करना चाहिये।

सभा की अध्यक्षता दिल्ली राज्य कमिटी के अध्यक्ष श्री डी.एन. झा ने की। सभा को धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, महासचिव दिल्ली प्रदेश, श्री पी.एन. द्विवेदी, श्री धर्मेन्द्र कुमार (एड), श्री जहाँगीर, श्री महेश गुप्ता, श्री राजेश, श्री राम सुरत पाण्डे, श्री अनिल सांगवान आदि ने भी सम्बोधित किया।

नागपुर में देश प्रेम दिवस की धूम

नागपुर : 23 जनवरी 2009 को अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, नागपुर जिला कमिटी ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी का जन्म दिवस देश प्रेम दिवस के रूप में बड़े ही धूम-धाम से मनाया। नागपुर के लोहापुल स्थित नेताजी की प्रतिमा के पास प्रातः 9.30 बजे समारोह आयोजित किया गया । समारोह की अध्यक्षता साथी धर्मराज दूबे ने की। इस अवसर पर केन्द्रीय कमिटी सदस्य बलवंतराय मेहता तथा प्रदेश महासचिव अरूण वानकर प्रमुखता से उपस्थित थे।

तमिलनाडु के 16 जिलों में मना देश प्रेम दिवस

तमिलनाडु के 16 जिलों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्मदिवस 'देश प्रेम दिवस' के रूप में बड़ी धूम-धाम से मना। मदुरै में समारोह की अध्यक्षता वी.एस. नवामनी, चैन्नई में साथी मंजू गणेश, मदूरै पूर्व में साथी एम. मोहन, कोयम्बटुर में साथी राजाशेखरन, इरोड में साथी मुरूगावेल, डिंडीगुल में साथी जयरामन, पलानी में प्रो. गोपाल, तिरूप्पुवनम में साथी रमैया अम्बालम, तिरूनवेली में साथी थंगापाण्डियन आदि ने समारोहों को संचालकन किया। तमिलनाडु के कई स्थानों में जुलूस आदि का आयोजन किया गया, दिवारों को नेताजी के चित्रों से सजाया गया, हजारों रेंग-बिरंगे पोस्टर पूरे तमिलनाडु में चिपकाये गये।

पूँजीवाद संकट का समाधान नहीं : समाजवाद एकमात्र विकल्प

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

(लुम्बिनी, नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-एमाले के 16-21 फरवरी 2009 के आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया भाषण)

सबसे पहले मैं अपनी पार्टी अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से अपनी हार्दिक शुभकामनायें। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की आठवीं राष्ट्रीय सम्मेलन को देना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पार्टी के इस सम्मेलन में श्रमिक हितों के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय किये गए हैं और समाजवाद की ओर बढ़ने की दिशा में कई निर्देश और निकल कर आए हैं।

जहां तक हम सब इस बारे में जानते हैं कि यह सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब दुनिया आर्थिक मंदी से बेहाल है। सबसे दुखद बात यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था के समक्ष उपस्थित यह संकट उन लोगों के कष्टों को और बढ़ानेवाला साबित होगा जो पहले से ही तथाकथित आर्थिक विकास की दौड़ में हासिए पर धकेल दिए गए हैं।

अब तो यह भी प्रमाणित हो गया है कि कि अर्थव्यवस्था का यह पूंजीवादी मॉडल धोखाधड़ी, साठगांठ और बेहद षोषण के आधार पर पूंजीपतियों द्वारा अत्यधिक पूंजी जमा करने पर ही जोर देता है। विकसित देशों की सरकारें भी अपने देष की अर्थव्यवस्था में उछाल बनाए रखने के लिए इन पूंजीपतियों को इस तरह के शोषण और धोखाधड़ी को न केवल अनदेखा करती हैं बल्कि इसमें उन्हें सहयोग और प्रोत्साहन भी देती हैं। इस बारे में अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि कैसे पूंजीपतियों द्वारा चलायी जा रही इस व्यवस्था में गरीबों का षोषण होता है। अब तो यह भी साबित हो चुका है कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आर्थिक क्षेत्र में मॉडल ढांचागत समायोजन नीति मूलतः विकासशील और अविकसित देशों को अपने शिकंजे में रखने के लिए ही बनायी गयी है।

इस नीति का उपयोग इन देशों के धन को खींचने के लिए उपकरण के तौर पर हुआ है। आर्थिक और ढांचागत स्तर पर इस तरह के प्रपंच के कारण इन देषों का सामाजिक विकास का स्तर नीचे गिर गया है। वैश्विकरण की यह नीति और प्रक्रिया से आर्थिक असमानता अपने चरम पर पहुंच गया है, गरीबों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है और सारी संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जमा हो गयी है। अब विकसित पूंजीवादी देशों का पूरा जोर पूरी तीसरी दुनिया के देशों पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक आधिपत्य कायम करने की ओर है।

यह भी तथ्य है कि 21वीं शताब्दी में करीब 80 करोड़ लोग भुखमरी के षिकार हैं, 20 करोड़ बच्चे अमानवीय स्थिति में जीवन गुजार रहे हैं और करीब 11.50 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में कर्जों के कारण गरीबी, शोषण बढ़ रहा है और उनकी निर्भरता सेना पर बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विकसित देशों में जहां औसत आयु 71 वर्ष है वहीं तीसरी दुनिया के देशों में यह लगभग 38 वर्ष है। बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। वर्तमान की मंदी इन संकटों और आगे और बढ़ाने ही वाली है। सभी देशों में जहां तक हमारा अनुभव है वैश्विकरण का यही असली चित्रण है।

पूरी दुनिया के कामगारों, किसानों और युवाओं की विशाल फौज के सामने एक नये तरह का विश्वास पनप रहा है। हर कहीं एक तरह की सोच रखनेवाले श्रमिक वर्ग इस नीति का विरोध कर रहे हैं, शिकार बनने से इनकार कर रहे हैं और राजनीतिज्ञों की अक्षमता से खाली हुए राजनीतिक क्षितिज का उपयोग कर, अपनी दृष्टि का परिष्कार कर, पढ़-लिखकर और आपस में बहस विचार के द्वारा वह दुनिया को नये तरह से फिर से व्यवस्थित करने के बारे में सोच रहे हैं। नेपाल और भारत के श्रमिक वर्ग द्वारा किये जा रहे आंदोलन इसी वैश्विक आंदोलन के हिस्से हैं।

दुनिया बेसब्री से उन आवाजों की ओर भी देख रही है जिन्होंने समाजवाद के अंत की घोषणा की है और पूंजीवाद को एकमात्र विकल्प के तौर पर बनाने की वकालत कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा, एक मानक जीवन स्तर, समुचित स्वास्थ्य सेवा और अच्छे जीवन यापन, जिनमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार व शिक्षा की गारंटी भी शामिल है, के लिए पूरी दुनिया में जनांदोलन छिड़ा हुआ है। इस क्रम में यह भी साबित हो चुका है कि पूंजीवाद इन जरूरतों को पूरा करने में न केवल अक्षम है बल्कि वह इसे और बढ़ा ही रहा है। इसलिए समाजवाद के लिए जन उभार आज और तेज हो चुका है।

जब आप महलों की सर्वसत्तावाद से जनता के जनवाद की ओर ऐतिहासिक संक्रमण के दरवाजे पर खड़े हैं, हम अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक के विचारों को माननेवाले लोग गंभीरता से इस बात में विश्वास करते हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेपाल की जनता की तकदीर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने की ताकत रखती है। भारतीय वामपंथ के प्रखर विचार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष के दौर में ही यह रेखांकित कर दिया था कि हर देश को अपनी जरूरतों, और परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद का अपना समुचित ढांचा गढ़ना चाहिए।

जमीनी हकीकत को जाने बिना ही किसी व्यवस्था को हू-ब-हू स्वीकार कर लेना वस्तुत बहुत बड़ी आपदा है। उन्होंने कहा कि जब आप जनाकांक्षाओं के अनुरूप एक जनोन्मुखी व्यवस्था का इजाद करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। आप 2010 तक जो संविधान बनाने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके जनता और प्रशासन की भूमिका और राष्ट्र के चरित्र का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन इसके साथ ही संविधान को समुचित तरीके से लागू करना, जनता की मांगों पर विचार करना और लोगों की आवाज को सुनना राजनीतिक इच्छाशक्ति के लिए बहुत ही जरूरी चीजें है। हमारा पूरा विश्वास है कि नेपाल की अति प्रगतिशील नेकपा - एमाले इन पक्षों पर अच्छी तरह से विचार करेगीं। वह भी न केवल संविधान बनाने के समय बल्कि इसके क्रियान्वयन के समय भी।

नेकपा-एमाले का यह आठवां राष्ट्रीय सम्मेलन न केवल नेपाल के ऐतिहासिक बदलाव में मील का पत्थर साबित होगा बल्कि विश्व श्रमिक वर्ग के आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नेकपा-एमाले वैश्विक मजदूर जनांदोलन और उनके अधिकार तथा समाजवाद का अभिन्न हिस्सा है। हम आशा करते हैं कि सम्मेलन की प्रतिबद्धता सारी दुनिया के प्रगतिषील तबकों द्वारा चलाये जा रहे समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के संयुक्त आंदोलन को और मजबूत करेगा।

अंत में हम एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक मानवता के लिए आपके द्वारा चलाये गये हर संघर्ष में अपना कंधा मिलाता रहेगा।

भारत- नेपाल की जन मैत्री-अमर रहे !

नेकपा-एमाले और फॉरवर्ड ब्लॉक की मैत्री - अमर रहे !

साम्राज्यवादी-पूँजीवादी व्यवस्था का घृणित खेल

आज हमारा देश एक ऐसी हालात में पहुँच गया है जिसमें हमारा कुलीन वर्ग इन साम्राज्यवादी पूँजीवादी ताकतों का दलाल जैसा हो गया है। अवाम के घोर शोषण वाली व्यवस्था में अब धन कुबेरों की भीड़ जैसी हो गयी है। जिसको देखो वह दुनिया के श्रीमंतों की फहरिश्त में अना नाम लिख रहा हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा कहाँ से आया ?पूछे भी क्या जब वह खुदी उसी लाईन में लगा अपने नंबर का इन्तजार में हैं। सो हमारे ये नेता भारत में पैसा कैसे रखें कहीं कोई कुत्ता सूंघ न ले और सब उलट पुलट न हो जाये। सो सैकड़ों हजारों अधिकारी स्विजरलैण्ड की तीर्थ यात्रा करते हैं। अपना पैसा वहाँ की बैंकों में जमाकर भरोसे की सांस लेते हैं क्योंकि वहां के कानून में उस बैंक का हिसाब कोई देख नहीं सकता है। यह खेल बहुत दिनों से चल रहा है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होने जा रहा है कि किसी देश की सरकार अपने नागरिकों के खातों के बारे में जानकारी ले सकती है। मसौदे का अंतिम रूप देने के बावजूद अभी भारत सहित कुछ देश उस पर अंतिम सहमति नहीं दे पाये हैं।

महा यह है कि स्विट्जरलैण्ड की बैंक के एसोसिएशन ने उन बैंकों में जमा पूँजी का ब्यौरा दिया हैं। उसके अनुसार **भारतीयों की जमा पूँजी 1446 बिलियन डॉलर है जो अन्य देशों की कुल जमा राशि से अधिक है।** रूस दूसरे नंबर पर है। जाहिर है कुछ मानवीय अपवादों को छोड़ भारत के कुलीनवर्ग की बचत सब स्विट्जरलैण्ड में हैं यदि वह भारत में निवेश हुई होती तो हमें भला औरों के सामने हाथ पसारने की जरूरत ही क्यों पड़ती। भारत सरकार अभी समझौते पर दस्तखत इसीलिये नहीं कर रही है कि सभी तो उसमें बेनकाब हो जायेंगे।

इसी पैसे की ताकत से भारत की समूची प्राकृतिक संपदा पर पैसे वालों का सीध या बेनामी कब्जा हो रहा है। भारत को दलाल शायक वर्ग भी इसमें पीछे नहीं है - किसी भी कीमत पर खेती की जमीन सहित संसाधनों पर कब्जा करने के लिये आमादा है। भूमि से बेदखल किसान और मजदूर कहां जायेगा। इसकी कहीं किसी को कोई परवाह नहीं। कोई कहता है कि उद्योग लगेगा तो रोजगार मिलेगा। यह सरासर झूठ है। आज औद्योगिकर ऋणात्मक रोजगार वाला है यानी ऊँची तकनीक के कारण जितने लोगों को रोजगार मिलता है, उससे अधिक लोक बेरोजगार होते हैं। इस तरह उद्योग से रोजगार मिलेगा, यह सबसे बड़ा धोखा है।

आम आदमी को क्या मिला?

संसद के संयुक्त अधिवेशन में 12 फरवरी 2009 को दिया राष्ट्रपति का अभिभाषण जितना बोझिल था, गरीबों और आम आदमी के लिए उतना ही निराशाजनक भी। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सबसे मौजूदा प्रश्न को उठाया -आम आदमी को क्या मिला ?लेकिन जो आम आदमी है वह उनके द्वारा दिए जवाब से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। अभिभाषण में कहा गया 'सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लोगों से किए लगभग हर वायदे को पूरा कर दिया।' यह उद्घोषणा कर सरकार 'अपने मुंह मियां मिट्ठू' तो बन सकती है लेकिन असलियत यह है कि 'शिक्षा का अधिकार' और संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का विधेयक अब भी संसद में लंबित पड़ा हुआ है। विधेयक की आवाज संभव है चुनाव अभियान के दौरान जोर-शोर से उठे लेकिन केवल विधयेक पेश कर देने से जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। हमारी आबादी की 30 फीसदी से अधिक आबादी अब भी निरक्षर है और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक अधिकार अब भी बहुत कम मिले हुए हैं। यह भी सवाल उठाया जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बावजूद रोजगार के अधिकार की गारंटी अभी कितनी दूर है। बेरोजगारी और गरीबी स्तर अब भी बढता ही जा रहा है। हालिया वैश्विक मंदी की वजह से हमारे देश में कम से कम 7 लाख नौकरियां चली गयी हैं। कानून होने के बावजूद असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे करोड़ों कामगार अब भी सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से महरूम हैं और देष की करीब 78 फीसदी आबादी आज भी 20 रुपये प्रतिदिन की आय से गुजर-बसर कर रही है। दुर्भाग्य से माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के इन कठोर तथ्यों का कहीं उल्लेख नहीं था। इसकी जगह इसमें कार्यकाल पूरा कर रही संप्रग सरकार के कार्यो को गिनाने की कोषिषें ज्यादा दिखीं। यह अभिभाषण सही मायनों में आम आदमी की स्थितियों का आकलन करने की जगह सरकार का चुनावी घोषणा पत्र भर बन कर रह गया।

कृषि उत्पादन में लगातार बढोतरी के दावों के बावजूद देश बाहर से खाद्यान्न आयात करने पर अधिकाधिक निर्भर है, जिसे हमारी खाद्यान्न सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इससे भी अधिक, अगर उत्पादन इतना ही अधिक हो रहा है तो क्यों नहीं जन वितरण प्रणाली के माध्यम से इन्हें बांटा जा रहा है।

नई शुरू हुई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन करोड़ों गरीब लोगों की बीमारियों और अस्वस्थता को खत्म करने में नाकाम है। इसके विपरीत, देश में कुछ पैसेवालों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पैसे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में यह हमारे समाज की मौलिक असमानता है, जो पूरे विकास में की गति में बाधा बनी हुई है। लेकिन सरकार इसे ही विकास कहती जा रही है।

जिस विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को संप्रग सरकार अपनी अपूर्व उपलब्धि बताते नहीं थक रही, वह असलियत में हाल फिलहाल में काफी मात्रा में जमीन हड़प रहा है। यह सेज अपनी प्रकृति से ही शोषक है और इससे एक विशेष सुविधाभोगी वर्ग तैयार हो रहा है जो कर और शुल्कों से छूट का जमकर उपभोग कर रहा है। निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन के नाम पर सेज के लोग देश के संसाधनों का दोहन अनेक सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। कुल विकास के हित में होगा कि इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए।

अभिभाषण में अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों की मजबूती का प्रदर्षन करते हुए भारत-अमेरिकी परमाणु करार को जोर-शोर से उठाया गया, लेकिन हमें डर है कि इससे कहीं हमारे देश के लिए नुकसानदायक न साबित हो जाए। अमेरिका का परमाणु रिएक्टर का पूरा कारोबार ही हमारी कीमत पर चलनेवाला है। ठीक इसी तरह अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी से भारत की गुट निरपेक्षता की संचित छवि खत्म हो जानेवाली है। इससे हमारी स्वतंत्र विदेश नीति पर खतरा आनेवाला है। संप्रग सरकार ने उत्कट आषा व्यक्त की है कि 'हमारे युवा इससे पहले अपने भविष्य के प्रति इतना आशान्वित कभी नहीं हुआ', लेकिन अभिभाषण में कही गयी इस बात को गले के नीचे उतार पाना मुश्किल है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, बीमारी और निरक्षरता, जन वितरण प्रणाली की असफलता, छिनती नौकरियों का भय हमारी युवा पीढी को निरंतर सता रहा है। अच्छा यह होगा कि हमारे इन वस्तुपरक आकलन से सहमत होकर देश के समाजवादी ढंग से पुनर्निर्माण में इसका समाधान ढूंढा जाए।

आम आदमी को क्या मिला?

जयन्त वर्मा

1950 में भारत के नागरिकों ने संविधान को अंगीकृत किया जिसमें आपातकाल के दौरान संशोधन करके 'समाजवादी' समाज व्यवस्था कायम करने का संकल्प जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ है देश के सभी नागरिकों में समाज के भौतिक संसाधनों का बराबरी से बंटवारा तथा उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के कल्याण की दृष्टि से प्रबंधन। 58 वर्ष बीतने के बाद केन्द्र सरकार के एक आयोग ने असंगठित वर्ग के नागरिकों के जीवनस्तर का अध्ययन करे जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार आबादी का 6.4 प्रतिशत 9 रु० से कम पर, 16.4 प्रतिशत 12 रु०, 19 प्रतिशत 15 रु० और 36 प्रतिशत 20 रु० से कम प्रतिदिन आय पर गुजारा कर रहा है। निचोड़ यह कि 77 फिसदी आबादी की प्रतिदिन आमदनी 20/- रु० से कम है। गरीबी उन्मूलन का आजादी के बाद का सबसे बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाया जा रहा है। इसके लिये 16000 करोड़ परिवारों को काम के बदले पारिश्रमिक के रूप में बांटा जा रहा है। 20/- से कम आय पर गुजारा कर रही देश की 83 करोड़ (77 प्रतिशत) आबादी में यदि यह धनराशि बांट दी जाये तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में प्रतिदिन 33 पैसा आयेगा। जाहिर है इससे गरीबी दूर नहीं होगी। केन्द्र सरकार ने समाज में निर्धनता उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम चला रखे हैं। जिन्हें राज्य सरकारें स्वयं या अपने चहेते स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लागू करती या पचा जाती हैं।

संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों के मूलाधिकार में समानता के सिद्धांत की उद्घोषणा करता है। संगठित वर्ग और सरकारी कर्मचारियों को परिवार के भरणपोषण के योग्य वेतनमान दिया जाता है, जो छठवें वेतन आयोग के अनुसार प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह होगा। आबादी का 85 फीसदी असंगठित वर्ग से है जिसके लिये संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार व्यक्तिगत निर्वाह योग्य वेतन तय है। राज्य की यह मान्यता है कि असंगठित वर्ग के परिवार के हर सदस्य को जीवित रहने के लिये अपने भरण-पोषण हेतु स्वयं परिश्रम करना होगा। घर किराया नहीं दिया जाता है इसलिये झुग्गी-झोपड़ी में पशुवत् जीवन गुजारना होगा। आजीवन काम करना होगा क्योंकि उसे पेंशन नहीं दी जाती। बीमार होकर सरकारी अस्पतालों से ठुकरा दिये जानो के बाद कीड़े-मकोड़ों की तरह मर जाना होगा।

इसी असंगठित वर्ग के कल्याण के लिये सरकार की लोकहितकारी योजनायें है। भरपेट वर्ग को पेटभर भोजन बांट देने के बाद जूंठन के बंटवारें की ये योजनायें समाप्त कर दी जाये और संसार के अन्य देशों की तरह भारत में भी संगठित और असंगठित वर्ग के लिये हकदारी का समान सिद्धांत और वेतनमाना तय कर दिया जाये तो ही वास्तव में जनकल्याण सुनिश्चित होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 43; मूलाधिकार के अनुच्छेद 14 तथा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के अनुच्छेद 23(3) का उल्लंघन करता है जिसमें सभी के लिये पारिवारिक आवश्यकता योग्य वेतन का प्रावधान है।

भारत की सभी रंग-रोगन की राजनीतिक पार्टियाँ पिछले 57 साल से गरीबी उन्मूलन के लिये जूझ(?) रही हैं। तमाम संवैधानिक पदाधिकारी, उच्च और उच्चतम न्यायालय भी गरीबी के संबंध में चिंतित हैं। इसके बावजूद देश में गैर-बराबरी बढ़ रही है। गरीबी के विश्वव्यापी मानदंड 2 डॉलर प्रतिदिन के आलोक में भारत की 80 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है किन्तु भारत के हुक्मरान खुश हैं कि देश 9 फीसदी की दर से आर्थिक वृद्धि हासिल कर रहा है। यह वृद्धि समाज के मलाईदार वर्ग की, मलाईदार वर्ग द्वारा और मलाईदार वर्ग के लिये गठित और संचालित है।

विषमता को खत्म कर समाजवादी समाज व्यवस्था कायम करने के लिये शहरी और ग्रामीण आबादी हेतू बजट में आबादी के आधार पर आनुपातिक आबंटन करना होगा। अनाज का समर्थन मूल्य तय करने में किसान के पारिश्रमिक की गणना संगठित वर्ग के समतुल्य करना होगा। जाहित है भारत का कोई भी राजनीतिक दल इसके लिये तैयार नहीं होगा, क्योंकि सभी दल मलाईदार वर्ग की भलाई के लिये गठित है। स्लमडॉग मिलिनेयर जैसी फिल्मों के बहाने कभी-कभी असंगठित वर्ग के जीवन की त्रासदी पर चर्चा के लिये मलाईदार वर्ग के तथाकथित बुद्धिजीवियों और मीडिया को चर्चा का अवसर मिल जाता है। बढ़ती गरीबी और गैर बराबरी को जड़-मूल से खत्म करना किसी भी राजनीतिक दल की कार्यसूची में नहीं है क्योंकि यथास्थिति बनाये रखने वाली स्वयस्था का पोषण करते हुये मलाईदार और शोषक वर्ग का हित साधन करना सभी का एकमात्र लक्ष्य है।

दीनहाटा के शहीदों की याद में, कोलकाता रैली

5 फरवरी 2008 का दिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन था। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक सप्ताह पर्यन्त पश्चिम बंगाल राज्य के सभी जिलों में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की ओर से बंगाल समिति ने जन आंदोलन के कार्यक्रम जिसमें धरना, प्रदर्शन, सभायें आदि का आह्वान किया था। इन कार्यक्रमों के जरिये सात महत्वपूर्ण माँगे रखी गयी जिसमें कानून के तहत सौ दिन का काम, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीने वालों की वास्तविक दशा के आधार पर सूची बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब कार्डों का जारी करना और दलितों के विकास हेतु चलाये जाने वाले विकास कार्य शामिल थे। ये सभी माँगें गरीब लोगों के जीनके के अधिकार पर आधारित थे। सप्ताह पर्यन्त चलने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रम के समापन के बाद 5 फरवरी 2008 को एक दिन का शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा का कार्यक्रम सभी जिलों में चलाया गया। इस कार्यक्रम के आह्वान पर हर जिले में बहुत से लोग जुटे। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुयी सिवाय कूचबिहार जिला के दीनहाटा के दु:खद शर्मनाक घटना के। वहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीआरपीएफ और पुलिस ने बर्बरता पूर्वक आक्रमण कर दिया और फलस्वरूप पाँच नौजवान प्रदर्शनकारी शहीद हो गये। पुलिस की इस निर्मम बर्बर कार्यवाही के विरोध स्वरूप अगले दिल पूरे राज्य में बंद का आह्वान हुआ जिसे पूरी तरह सफल पाया गया।

5 फरवरी 2008 को दीनहाटा में मारे गये 5 शहीदों की याद में कोलकाता के इस्टलेण्ड में दस हजार लोग एकत्रित हुये। पड़ोसी जिलों के अनेक पार्टी कार्यकर्ता इस विशाल सभा में एकत्रित हुये जिन्हें कई नेताओं के अतिरिक्त साथी अशोक घोष, फारवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल समिति के महासचिव ने भी संबोधित किया।

उस दिन दीनहाटा में जहाँ एक वर्ष पूर्व यह दु:खद घटना हुई थी उसी दिन दीनहाटा में ऐसी ही विशाल रैली आयोजित हुई।

पूँजीवादी लोभ असीमित : लाखों बेरोजगार

डॉ. बरूण मुखर्जी, सांसद

अधिक और अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति जिससे अमेरिका के विशाल बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र को भयावह ऋण संकट से गुजरना पड़ा और जिससे अभी वह उबर नहीं सका और स्वयं गंभीर आर्थिक संकट में पड़ चुका है साथ ही उसने पूरी दुनियाँ को भी इस संकट में घसीट डाला है। अमेरिकी पूँजीवादी से जुड़े अनेक देशों के शेयर बाजार धराशायी हो गये और सट्टा शेयर बाजारोन्मुख तथाकथित आर्थिक विकास जैसा पूँजीवाद को प्रश्रय और बल देने वाले भारत समेत अन्य अनेक शासक वर्ग के द्वारा जैसा प्रचारित किया जाता रहा है और इससे प्रभावित आम जन मानस की विश्वा गहरे अवसाद में डूब गया। आयी यह विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जिसकी शुरूआत अमेरिकी पूँजीवादी घरानों से हुई - पूँजीवाद जनित समस्या है जिसके सामान्य जन के जीवन के पर गंभीर भयावह दुष्परिणाम पड़ना अवश्यमभावी है। सबसे बुरा असर चारों ओर नौकरी से हो रही छंटनी और दुनियाँ के भिन्न-भिन्न भाग से लाखों लोगों के बेरोजगार होने में देखा जा सकता है।

परंतु पूँजीवादी लोभ का सबसे बुरा घृणित पक्ष यह है कि इस भयावह आर्थिक मंदी के दौर से भुगत रही जनता के प्रति वह कोई नरमी नहीं बरत रहा है, उसका लोभ संवरण नहीं हो रहा है। ऐसा स्वयं अमेरिका में हाल में हुई घटना से स्पष्ट हो गया और नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने देश के लालची बैंकरों की कटु आलोचना कर डाली। ओबामा ने ढहती अर्थव्यवस्था और जर्जर हा चुके आर्थिक तंत्र/संस्थाओं के राहत के तौर पर बीस अरब डालर की बोनस राशि देते हुये वाल स्ट्रीट के बैंकरों को शर्मनाक होने की तोहमत लगायी। ओबामा ने आगे कहा कि "अनेक बैंकरों के लिये मुनाफा कमाने का समय आयेगा, बोनस पाने का समय भी आयेगा, परन्तु इन सबके लिये यह समय उपयुक्त नहीं हैं और ऐसा संदेश मैं उन्हें प्रेषित करता हूँ।" इस प्रकार ओबामा ने अपने गुस्से का इजहार किया जो उनके चारों तरफ आई परिस्थिति में लाजमी है। जनवर 2009 के अंतिम सप्ताह में अकेले 65000 लोगों की नौकरी से छंटनी हुई। अमेरिकी जनता का गुस्सा बैंकों और निवेश आयोजित करने वाली संस्थाओं के अनियमित फिजूल खर्च के प्रति उफन पड़ा। जबकि इन्हें पर्याप्त राहत धनराशि सरकार से मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि आर्थिक मंदी गहरा रही है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार वर्तमान जनवरी-मार्च 2009 का काल सर्वाधिक दुष्प्रभावित काल होगा।

अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार जनवरी 2009 में लगभग 6,00,000 (छः लाख) लोगों ने नौकरी से हाथ धोयें हैं और विगत 16 वर्षों में बेरोजगारी का दर 7.6 फिसदी के सर्वोच्च स्तर पर रहा है। दिसम्बर 2008 तक 5,77,000 अधिकारिक आँकड़ों के अनुसार बेरोजगार हुये। अन्ततः अमेरिकी सरकार ने स्वीकार किया कि दिसम्बर 2007 से शुरू हुये मंदी के दुष्प्रभाव से अब तक 36 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं।

इस भयावह मंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार की संभावना पर भी पड़ा। पूरी दुनियाँ के स्तर पर जनवरी 2009 में औसतन 9000 लोग प्रतिदिन बेरोजगार होते रहे हैं। भारत में अक्तूबर से दिसम्बर 2008 तक अनुमान है कि करीब 5 लाख लोग बेरोजगार हुये। अपने अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने स्वयं स्वीकारा कि भारत पर भी मंदी का दुष्प्रभाव पड़ रहा है और जनवरी से मार्च 2009 तक और भी लोग बेरोजगार होंगे।

आयी आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव को कम करने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिसम्बर 2008 और जनवरी 2009 के जारी आर्थिक राहत पैकेज का असर नहीं रहा और नौकरी से छंटनी प्रवृत्ति कम नहीं हुयी। ऑटोमोबाइल, मेटल, ट्रांसपोर्ट, निर्माण और माइन्स, टैक्सटाइल, जेम्स और ज्वैलरीज और संचार जैसे आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो निर्यात में काफी नुकसान उठा रहे हैं। गत् तीन माह में इन्होंने निर्यात में 3.45 फीसदी आय में कमी दर्ज की। ऐसा लगता है कि जीडीपी विकास दर बुरी तरह प्रभावित होगी। भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध है और मंदी के दंश को अनुभूत कर रहा है। 1 करोड़ नौकरियों से वर्ष 2008-09 में हाथ धोना पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल में जनजातियों का सम्मेलन

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के बंगाल समिति के नेतृत्व में 28-29 जनवरी 2009 को पश्चिम बंगाल के बाँकुरा में जनजातियों (आदिवासियों) का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। जन जातियों को लेकर पार्टी कुछ वर्षों से क्रियाशील थी और उनके आन्दोलन चला रही थी। परन्तु, 'अग्रगामी आदिवासी समिति' जो पार्टी का नव निर्मित जन मोर्चा है के तत्वावधान में 18 जिलों के 250 आदिवासी प्रतिनिधि के सक्रिय भागीदारी में राज्य स्तर का दो दिवसीय कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ। 28 जनवरी 2009 को बाँकुरा शहर के ताम्लीबंध मैदान में आयोजित रंगारंग खुले ऐतिहासिक सत्र की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस रैली में उपस्थित दस हजार आदिवासीा अपने परम्परागत वाद्य यंत्र और तीर-धनुष के साथ थे।

दो दिवसीय इस सत्र में अनेक ज्वलंत विषयों पर चर्चा हुयी तथा राज्य के 50 लाख आदिवासी आबादी की समस्याओं पर विचार हुआ और कार्यक्रम (गतिविधियों) की एक वर्ष की रूपरेखा तय हुई। 39 सदस्यीय राज्य समिति का गठन साथी जतिन सोरेन और साथी निशिकान्त मेहता संयुक्त अध्यक्ष और साथी बिश्वनाथ किस्कु और साथी रेवती भट्टाचार्य संयुक्त महासचिव बनाये गये।

21-सूत्रीय चार्टर की माँग पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसमें जल-वन-भूमि का फारेस्ट ड्वेलर एक्ट के तहत अधिकार लागू करने की माँग की गयी, भूमिहीन आदिवासी किसानों को खेती हेतु जमीन उपलब्ध कराने की माँग की गयी। आदिवासियों के लिये राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड मुहैया करायी जायें, अक्षम वृद्ध पुरुष व महिला को मासिक 500 रु० की पेंशन की व्यवस्था की जाने की मांग की गयी; हर आदिवासी गाँवों में मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और चिकित्सा-केन्द्रों सुलभ कराये जाने की मांग की गयी; बिजली, पेयजल सभी सभी आदिवासी गाँवों में पहुँचे तथा हर परिवार को जनजाति प्रमाण प्रदान किया जाये। स्वतः मददगार समूह, सहकारिता, ट्रेनिंग जिसमें स्टारपेंड राशि आदिवासीा जिलों में दी जाये। जन-जातिय भाषा व सभ्यता के विकास के साथ अलचिकी प्रारंभिक अक्षर का विकास हो; छोटे-छोटे सिंचाई के साधन, बीज, खाद, कीटनाशक उपलब्ध कराये जायें। लघु, कुटीर उद्योग जिसमें बाजार उपलब्धता की सुविधा हो और सभी जनजातिय विकास समितियों में स्थान आरक्षण की सुविधा हो, की मांग की गयी।

चुनाव आयोग में सुधार की दरकार

अतुल कुमार

चुनाव आयोग के अंदर हाल में छिड़ी जंग से यह साफ हो गया है कि कई चुनावों में सफलता के झंडे गाड़नेवाली इस संवैधानिक संस्था में सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। इस संस्था के संचालन के प्रावधानों में कई खामियां हैं जिन्हें उभारकर ठीक करने की निहायत ही जरूरत है।

हालिया घटना में एक चुनाव आयुक्त नवीन चावला के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिछले साल नोटिस जारी किया और उनसे कुछ मुद्दों पर सफाई मांगी थी। लेकिन चावला ने जवाब नहीं दिया। अब जबकि आम चुनाव नजदीक है और मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी रिटायर होनेवाले है, उन्होंने चावला को बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। लेकिन दो दिनों बाद ही केंद्रीय विधिमंत्री हंसराज भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नवीन चावला का न केवल बचाव किया है बल्कि उन्हें अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का भी संकेत दे दिया है।

यहां इस पर विचार करना जरूरी है कि संविधान में क्या प्रावधान है और वर्तमान विवाद की जड़ कहां है?संविधान में चुनाव आयोग को एक स्वायत्त संस्था बनाया गया है ताकि दलीय हस्तक्षेप से यह मुक्त होकर अपना काम करे। षुरू में टी.एन. शेषन के कार्यकाल तक एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था और चुनावों में उसकी कोई अहमियत कभी सामने नहीं आती थी। शेषन के काल से आयोग ने अपने अधिकारों का प्रयोग करना शुरू किया तो विवाद भी सामने आने लगे। इसी क्रम में सरकार ने संविधान संशोधन कर चुनाव आयोग को एक सदस्यीय से बढ़ाकर तीन सदस्यीय बना दिया और तीनों आयुक्तों को समान अधिकार का प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 (3) में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया बतलाइ गई है वह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी है। यानि संसद में महाभियोग के जरिए उसे हटाया जा सकता है। अन्य आयुक्तों के बारे में वहां कुछ नहीं इसलिए है कि तब चुनाव आयोग एक सदस्यीय हुआ करता था। बाद में संविधान संशोधन में प्रावधान जोड़ा गया कि अन्य आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त से सलाह लेना जरूरी होगा। हालांकि संविधान में इसके लिए महाभियोग या इंपिचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन इस अनुच्छेद की व्याख्या से साफ है कि राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त से किसी आयुक्त हटाने के लिए परामर्श मांगेगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी ओर से इसकी पहल करने का अधिकार नहीं है।

यह हुई संविधान की बात। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान क्या है?यहां नजर डालें तो कड़ी बिल्कुल ही कमजोर है। जहां आयुक्तों को हटाने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा है तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी इतनी ही पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा है नहीं। वर्तमान नियम के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार द्वारा राष्ट्रपति को भेजे पैनल में से होती है। यहां सत्ताधारी पार्टियां अपने चहेतों को चुनाव आयोग में बैठा देती हैं। एन. गोपालस्वामी राजग शासन में भाजपा के चहेते के तौर पर आए थे तो संजय ब्रिगेड से राजीव गांधी की टीम में आए नवीन चावला कांग्रेस की पसंद रहे हैं। इस समय भी दोनों अपने-अपने आकाओं को प्रसन्न करने के खेल में हैं और इसके छींटे पड़ रहे हैं संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर।

तो क्या इस तरह का विवाद उभरना ही नहीं चाहिए था?वर्तमान विवाद में चारो ओर से उठ रहे स्वर तो यही मांग कर रहे हैं कि इस विवाद को उठना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि विवाद न उभरने से यही नासूर आगे भी बना रहेगा और कभी विकराल रूप भी ले सकता है। इसलिए इस तरह की संस्थाओं की सीमा और खामियों को उजागर करता हुआ जो भी विवाद उभरे उसका स्वागत किया जाना चाहिए बषर्ते व्यवस्था उसका सही समाधान करने की इच्छाशक्ति रखती हो।

यहां जो भी विवाद उठा है उसका उपचार किया जाना चाहिए न कि इस बात पर शोर मचे कि यह विवाद उठा ही क्यों?चुनाव आयोग को जो स्वायत्ता मिली है और आयुक्तों को हटाने का जो कठिन प्रावधान है, उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए ताकि आयुक्त निष्पक्ष रहकर काम कर सकें। अब इन आयुक्तों को राजनीतिक राग-द्वेष से मुक्त करने की दिशा में हमारी राजनीतिक व्यवस्था को पहल करनी चाहिए ताकि आगे गोपालस्वामी और चावला जैसे नौकरशाहों को इस संस्था में प्रवेश न हो सके।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सर्वदलीय समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि, सुप्रीम कोर्ट के जज और कुछ विशेषज्ञ भी शामिल हों। समिति में पार्टियों का प्रतिनिधित्व संसदीय स्तर पर हो। यह समिति नौकरशाहों में से ऐसे का चयन करेगी जो किसी पार्टी से गहरे जुड़ाव न रखता हो। कुल मिलाकर आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार सरकार से लेकर संसद को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजों और विशेषज्ञों से बनी यह समिति ऐसे नौकरशाहों को रोकने में कामयाब हो जाएगी। इसके साथ ही चुनाव आयुक्तों के लिए भी प्रावधान हो कि वह सेवानिवृत्ति के बाद किसी लाभ के पद पर नहीं जा पाएगा और न ही सांसद विधायक बन पाएगा ताकि कोई मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्त किसी दल द्वारा सांसद बनाए जाने के लोभ में आकर कोई ओछी हरकत न कर पाए। ऐसा हो जाने पर चुनाव आयोग को और निष्पक्ष बनाया जा सकता है।

जनवादी कवि हरिहर ओझा 'तरण'

महाक्रान्ति का ताल,
समय का सरगम,
नूपुर परिवर्तन के,
और प्रगति की संगति पर,
जो जीवन नृत्य करेगा
नहीं मरेगा! नहीं मरेगा!

भारत का स्वाधीनता संघर्ष : सितंबर 1939 से अगस्त 1942 तक

सुभाष चन्द्र बोस

मई 1939 से फारवर्ड ब्लॉक का प्रचार-युद्ध पूरे जोरों पर था। उसी साल जुलाई में गाँधी पक्ष ने इसके इस काम को रोकने की कोशिश की। एक न एक आधार पर ब्लॉक के कई सदस्यों के खिलाफ कांग्रेस कार्यसमिति ने 'अनुशासन की कार्यवाही की'। लेकिन इससे उल्टा ब्लॉक के सदस्यों का मनोबर तो बढ़ा ही, जनसाधारण में इनकी लोकप्रियता भी और बढ़ी।

3 सितंबर, 1939 की बात है जब मैं मद्रास के समुद्र तट पर करीब दो लाख की भारी जनसभा के सामने भाषण कर रहा था। इतनी बड़ी सभा में मैंने इससे पहले कभी भाषण नहीं किया था। तभी श्रोताओं में से किसी ने मेरे हाथ में शाम का अखबार पकड़ा दिया। जब समाचार पत्र को पढ़ा तो पता गा कि ब्रिटेन ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर दी है। तुरंत ही मैंने विषय बदल कर युद्ध के विषय में बोलना शुरू कर दिया। जिस संकट की बहुत आशंका की जा रही थी अंतत: वह शुरू हो गया था। यह भारत के लिये एक स्वर्ण अवसर था।

जिस दिन ब्रिटेन के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया उसी दिन वाइसराय ने भारत को भी युद्धरत आंतरिक कर दिया और एक अध्यादेश जारी किया। जिसमें आंतरिक व्यवस्था को दबाने के लिये अत्यधिक कठोर शक्तियां सरकार को दी गयी थीं। 11 सितंबर को यह घोषणा की गयी कि 1935 के एक्ट के अधीन संघीय संविधान के उद्घाटन को युद्ध की अवधि संघीय संविधान के उद्घाटन को युद्ध की अवधि के दौरान स्थगित कर दिया गया था।

6 सितंबर को वाइसराय लार्ड लिनलिथगो से मुलाकात करने के बाद महात्मा गाँधी ने यह वक्तव्य दिया कि भारत की आजादी के बारे में भारत और ब्रिटेन के मतभेदों के बावजूद भारत को ब्रिटेन के संकट के समय उससे सहयोग करना चाहिये। गाँधीजी का यह वक्तव्य भारतवासियों के लिये एक बम के धमाके की तरह आया क्योंकि उन्हें तो 1927 से कांग्रेस नेताओं द्वारा यही पाठ पढ़ाया जा रहा था कि अगले युद्ध को भारत की आजादी प्राप्त करने का अभूतपूर्व अवसर माना जायेगा। गाँधीजी के इस बयान के बाद बहुत से गाँधीवादी नेताओं ने ऐसी सार्वजनिक घोषणायें करनी शुरू कर दी कि यद्यपि हम भारत की आजादी चाहते हैं पर यह भी चाहते हैं कि ब्रिटेन यह युद्ध जीते। क्योंकि इस तरह के प्रचार से भारत के जनमत पर बड़ा बुरा असर पड़ सकता था इसलिये फारवर्ड ब्लॉक ने, जो अब तक एक अखिल भारतीय संगठन बन चुका था, बड़े पैमाने पर इसका प्रतिकारक प्रचार आरंभ कर दिया। गाँधीवादियों के विपरीत फारवर्ड ब्लॉक इस बात का प्रचार कर रहा था कि कांग्रेस 1927 से बार-बार यह घोषणा करती आ रही है कि ब्रिटेन की लड़ाई में भारत को सहयोग नहीं देना चाहिये और अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपन इस घोषित नीति पर अमल करे। फारवर्ड ब्लॉक के सदस्य यह भी साफ कहते थे कि हम लोग युद्ध में ब्रिटेन की जीत नहीं चाहते क्योंकि ब्रिटेन के हार जाने पर ब्रिटिश साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर ही भारत आजाद होने की आशा कर सकता है।

फारवर्ड ब्लॉक के इस सामान्य प्रचार के अलावा मैंने देशभर का दौरा किया और दस महीने की अवधि में मैंने करीब एक हजार जनसभाओं में भाषण किये होंगे। इस बात का सभी को और मुझे भी आश्चर्य रहा कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन-विरोधी और युद्ध-विरोधी इतना भारी प्रचार होने कैसे दिया। सच्चाई यह है कि सरकार इस बात से भयभीत थी कि यदि फारवर्ड ब्लॉक के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाया तो कहीं कांग्रेस भी न भड़क जाये और आम जनता भी न भड़क उठे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह न शुरू हो जाये। सरकार की इस घबराहट का फारवर्ड ब्लॉक ने पूरा फायदा उठाया और वह ब्रिटेन और युद्ध के विरोध में अपना धुँआधार प्रचार करता रहा। हाँ, प्रचार के कारण बहुत से सदस्य जेल मे जरूर डाल दिये गये थे।

फारवर्ड ब्लॉक के इस प्रचार को सारे देश में खूब समर्थन मिला। तब महात्मा गाँधी और उनके अनुयायियों को भी महसूस हुआ कि अँग्रेजों से सहयोग की नीति को आम जनता का समर्थन नहीं मिलेका और इससे निश्चय ही वे अपना प्रभाव और लोकप्रियता खो बैठेंगे। परिणामस्वरूप उन्होंने धीरे-धीरे अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया।

गाँधीजी के रवैये से भी अधिक अजीब था पण्डित नेहरू का रवैया। 1927 से लेकर 1938 तक वह कांग्रेस के सभी युद्ध-विरोधी नीति के अगुआ रहेंगे। अपने पहले के प्रस्तावों के अनुसार कांग्रेस पार्टी को सितंबर 1939 के बाद तुरन्त ही ब्रिटेन से असहयोग कर देना चाहिये था और यदि इसके बाद सरकार युद्ध के लिये भारत का इस्तेमाल करती तो उसे ब्रिटिश सरकार के इस कदम का मुकाबला करना चाहिये था। पण्डित नेहरू ने इस नीति पर अमल ही नहीं किया, उन्होंने अपना सारा प्रभाव इस बात के लिये इस्तेमाल किया कि जब तक युद्ध चले तब तक कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार से परेशान न करे।

6 सितंबर को कांग्रेस कार्यकारिणी की वर्धा में इस बात पर निर्णय करने के लिये बैठक बुलाई गयी कि युद्ध के बारे में कांग्रेस को क्या रुख अपनाना चाहिये। मुझे, जबकि उस समय में कार्यसमिति में नहीं था, विशेष रूप से बैठक में आमंत्रित किया गया था और मैंने फारवर्ड ब्लॉक केक इस विचार को स्पष्ट रूप से सामने रखा कि आजादी के लिये हमें फौरन संघर्ष छेड़ देना चाहिये। मैंने बैठक में यह भी कह दिया कि यदि कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की तो फारवर्ड ब्लॉक, देश के हित में जो कुछ भी करना ठीक समझेगा, वह करने के लिये अपने आपको स्वतंत्र समझेगा।

इस दृढ़ रुख का प्रभाव पड़ा और गाँधी पक्ष ने ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने के अपने विचार को पूरी तरह छोड़ दिया। इसके बाद काफी लंबा विचार-विमर्श चला और अंत में 14 सितंबर को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक लंबा प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें ब्रिटिश सरकार से कहा गया था कि यदि भारत को स्वाधीनता दी जाती है तो 'एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिये खुशी से अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ देगा।'

यह प्रस्ताव, वास्तव में देखा जाये तो कुछ शर्तों के साथ ब्रिटेन के युद्ध प्रयत्नों में सहयोग देने का प्रस्ताव था।

17 अक्टूबर को वाइसराय ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव का एक वक्तव्य द्वारा उत्तर दिया जो लंदन में श्वेतपत्र के रूप में प्रकाशित हुआ। वाइसराय का प्रस्ताव भारतीय प्रतिनिधियों के साथ एक सलाहकार ग्रुप स्थापित करने का थो जो वाइसराय को लड़ाई के सवालों पर सलाह देता। वाइसराय ने भविष्य में कभी डोमानियन स्टेटस अर्थात औपनिवेशिक दर्जा देने का वायदे को भी दुहराया था। वह वायदा पहली बार दस साल पहले भारत के तत्कालीन वाइसराय लार्ड हैलीफाक्स (इर्विन) ने किया था।

ब्रिटिश सरकार के इस उत्तर के अलावा जिस चीज पर भारत की जनता में बेहद आक्रोश फैला व यह थी कि एक तरफ तो मित्र राष्ट्र स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिये लड़ने का दावा करते रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत में 1935 के विधान तक का भी स्थगित कर दिया गया था, सारी शक्तियां वाइसराय के हाथ में केन्द्रित कर दी गयी थीं, जैसे की छोटी-मोटी सभाओं और प्रदर्शनों की मनाही और बिना मुकदमा चलाये जेल में डालना इत्यादि।

मेरा यह निश्चित मत है कि यदि कांग्रेस ने मिलकर शुरू से ही युद्ध का दृढ़तापूर्वक विरोध करने का साहसपूर्ण और स्पष्ट रवैया अपनाया होता तो निश्चय ही भारत में ब्रिटेन के युद्ध के लिये आवश्यक उत्पादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और ब्रिटेन के लिये भारत की सेनाओं को देश से दूर-दूर के युद्ध के मोर्चों पर भेजना सम्भव

नहीं हो सकता था। मेरे विचार में इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध के बारे में कोई स्पष्ट और अंतिम निर्णय न करके गाँधी, नेहरू और उनके समर्थकों ने ब्रिटिश सरकार की अप्रत्यक्ष रूप में मदद की थी। जब कांग्रेस ने कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं प्रदान किया ता स्वाभाविक था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंटों ने जो प्रोपेगैंडा किया उसके चलते उन्हें भारतवासियों के कुछ वर्गों का सहयोग प्राप्त करने में सफलता मिली।

29 अक्तूबर को कांग्रेस कार्यसमिति ने वाइसराय के 17 अक्तूबर के प्रस्ताव का उत्तर दिया। उत्तर वाले प्रस्ताव में सत्याग्रह की धमकी दी गयी थी। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यसमिति ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों को आठों प्रांतों में अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया था। चूंकि वाइसराय प्रांतों की सरकारों को ब्रिटिश सरकार की युद्ध-नीति का पालन करने के लिये आदेश जारी कर रहे थे, अत: कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सामने यह विकल्प था कि या तो वे युद्ध प्रयत्नों में सहयोग दें या फिर अपने पद छोड़ दें।

आमतौर से यह आशा की जा रही थ कि कांग्रेस मंत्रियों के पद त्याग के बाद सत्याग्रह शुरू हो जायेगा। लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ ब्रिटिश लिबरल और डेमोक्रेटिक नेताओं को कांग्रेस नेताओं को प्रभावित करने के लिये भारत भेजा। उदाहरण के लिये अक्तूबर 1939 में प्रसिद्ध लेखक श्री एडवर्ड थामसन भारत आये और फिर उनके बाद दिसंबर में सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आये।

युद्ध मे सहयोग करने के खिलाफ और राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ने के पक्ष में फारवर्ड ब्लॉक निरंतर प्रचार करने के साथ-साथ ही इस बारे में जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिये यदाकदा प्रदर्शन भी करता रहा। उदाहरण के लिये अक्तूबर 1939 में नागपुर में एक साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन भी आयोजित किया गया जो काफी सफल रहा। छ: महीने पूरे होने पर ब्लॉक के प्रचार की परिणति मार्च 1939 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में विराट प्रदर्शन के रूप में हुई जो बहुत ही सफल रहा। इस प्रदर्शन को अ. भा. समझौता विरोधी सम्मेलन नाम दिया गया। इस प्रदर्शन को फारवर्ड ब्लॉक और किसान सभा ने मिलकर आयोजित किया था और यह रामगढ़ में कांगेस के अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, से अधिक सफल रहा।

रामगढ़ में भी कांग्रेस अपनी युद्ध-नीती के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकी। छ: महीने तक उसकी नीति स्पष्ट रही। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार युद्ध के लिये भारत के साधनों का पूरी तरह लाभ उठाती रही। रामगढ़ में समझौता-विरोधी सम्मेलन का नेतृत्व मैंने और किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और इसमें युद्ध तथा भारत की स्वाधीनता की मांग के मुद्दे को लेकर तत्काल संघर्ष शुरू करने का निश्चय किया गया। अप्रैल 1940 में राष्ट्रीय उत्साह (6 से 13 अप्रैल) के दौरान फारवर्ड ब्लॉक ने सारे देश में अपना सविनय अवज्ञा अभियान चलाया। ब्लॉक के प्रमुख नेताओं को धीरे-धीरे जेलों में ठूंस दिया गया। बंगाल में भी, जहाँ मेरा घर था, यह अभयान खूब फैला और जुलाई के शुरू में मुझे मेरे सैकड़ों साथी कार्यकर्ताओं समेत जेल भेज दिया गया।

जेल जाने से कुछ दिन पहले जून 1940 में मेरी महात्मा गाँधी और उनके सहायकों से अंतिम और लंबी बातचीत हुई। उस समय भारत में फ्रांस के हथियार डाल देने की खबर पहुँच चुकी थी। जर्मन सेनायें बड़े विजयोल्लास के साथ पेरिस में दाखिल हो चुकी थीं। इंग्लैण्ड और भारत में ब्रिटेन का मनोबल नीचा था। एक ब्रिटिश मंत्री ने ब्रिटिश जनता को मायूस और मातमी शक्लें बनाये रहने पर बड़ा लताड़ा था। भारत में फारवर्ड ब्लॉक ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वह चल रहा था और ब्लॉक के बहुत से नेता जेल जा चुके थे। अत: मैंने महात्मा जी से आगे आकर अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने की भावभरी अपील की क्योंकि यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश साम्राज्य अब खत्म हो जायेगा और भारत के लिये युद्ध में अपनी भूमिका अदा करने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन महात्माजी अब भी कुछ करने का वचन देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर अपनी वही रामकहानी दुहरा दी कि मेरी दृष्टि में देश संघर्ष के लिये तैयार नहीं है और इस समय यदि संघर्ष की नौबत लाई गयी तो लाभ की बजाय भारत को हानि अधिक उठानी पड़ेगी। खैर, बहुत लंबी और खुली बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि यदि भारत को आजाद करने के तुम्हारे प्रयत्न सफल होते हैं तो मैं (महात्मा गाँधी) तुम्हें बधाई का तार भेजने वाला सबसे पहला आदमी होऊंगा।

इस मौके पर मैंने अन्य संगठनों के नेताओं से भी बातचीत की, जैसे कि ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग के प्रधान मि. जिन्ना से, अ.भा. हिन्दू महासभा के अध्यक्ष श्री सावरकर से। उस समय श्री जिन्ना अंग्रेजों की मदद से पाकिस्तान की अपनी योजना को पूरा करने की सोच रहे थे। कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की आजादी के लिये राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करने के मेरे सुझाव का श्री जिन्ना पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा यद्यपि मैंने सुझाव दिया था कि यदि इस प्रकार मिल-जुलकर संघर्ष किया गया तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री वही बनेंगे। श्री सावरकर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ दिखाई देते थे और बस यही सोच रहे थे कि ब्रिटेन की भारत में जो सेना है इसमें घुसकर हिन्दू किस प्रकार सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करें। इन मुलाकातों के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुँचा कि मुस्लिम लीग या हिन्दू महासभा से किसी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती।

20 मई 1940 को पंडित नेहरू ने तो एक बड़ा ही आश्चर्यजनक वक्तव्य दे डाला जिसमें उन्होंने कहा कि 'ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन जीवन और मृत्यु के संघर्ष में लिप्त है उस समय सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आरंभ करना भारत के सम्मान के लिये घातक होगा।' इसी प्रकार महात्माजी ने भी कहा कि 'हम ब्रिटेन के विनाश के बदले अपनी आजादी नहीं लेना चाहते। यह अहिंसा का तरीका नहीं है।' यह साफ हो गया था कि गाँधीवादी लोग अँग्रेजों से समझौता करने की हर सम्भव कोशिश कर रहे थे।

27 जुलाई को अ.भा. कांग्रेस समिति ने पूना की बैठक में, जिसमें महात्मा गाँधी उपस्थित नहीं थे, इस शर्त के साथ कि यदि भारत की आजादी की कांग्रेस की मांग मान ली जाती है तो ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्नों में सहयोग करने का प्रस्ताव किया। इस समय महात्माजी कांग्रेस के नेतृत्व से अलग हो गये थे क्योंकि अहिंसा में अपनी आस्था के कारण उनके लिये युद्ध के प्रयत्नों का समर्थन करना कठिन था।

8 अगस्त को वाइसराय ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव का जवाब दिया जिसमें उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद में तथा सलाहकार परिषद में और अधिक भारतियों को लेने की पेशकश की, लेकिन यह तो स्वतंत्रता या उससे मिलती जुलती चीज भी नहीं थी।

इसी बीच मेरे बंदी बनाये जाने के बाद फारवर्ड ब्लॉक का प्रचार और जोरों पर चलता रहा जिसने गाँधी पक्ष के कार्यकर्ताओं को भी प्रभावित किया। इस आदेश के बावजूद कि गाँधी पक्ष के अनुयायी किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को नहीं चलायेंगे, इस पक्ष के कार्यकर्ताओं ने, विशेषकर स्वयंसेवकों ने कुछ प्रांतों में प्रचार करना आरम्भ कर दिया जिस कारण कई गाँधीवादी नेता चिन्तित हो उठे। इनमें से कुछ महात्माजी पर संघर्ष छेड़ देने के लिये दबाव डालने लगे। उनका कहना था कि ऐसा न करने पर देश में उनका प्रभाव और प्रतिष्ठा समाप्त हो जायेगी। कुछ ने तो आदेश मिलने की प्रतीक्षा किये बिना ही धीरे-धीरे इस संघर्ष में शामिल होना शुरू कर दिया। अंत में गाँधीजी को झुकना ही पड़ा। 15 सितंबर को कांग्रेस ने सहयोग के आश्वासन को वापस ले लिया और महात्माजी को कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिये बुलाया। अक्तूबर में गाँधीजी ने घोषणा की कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के युद्ध-प्रयत्नों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का फैसला कर लिया है। लेकिन यह आंदोलन बड़े पैमाने पर नहीं होगा। नवंबर 1940 में गाँधी जी का प्रचार शुरू हुआ और कुछ ही समय में आठ प्रांतों के सभी मंत्रियों को, जिन्होंने इसमें भाग लिया, कैद कर लिया गया और साथ ही सैकड़ों प्रभावशाली नेताओं को भी।

1940-41 का अभियान गाँधी ने उतने उत्साह और आवेश से नहीं चलाया जितने उत्साह से 1921 और बाद का 1930-32 का अभियान चलाया था। यद्यपि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाये तो देश अब पहले की अपेक्षा क्रांति के लिये कहीं अधिक तैयार था।

स्पष्ट था कि गाँधी जी अभी भी समझौते के लिये द्वार खुले रखना चाहते थे और इस आंदोलन के दौरान अँग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक कटुता पैदा हो जाती तो ऐसा करना पड़ा है। अब क्योंकि कांग्रेस के दोनों ही पक्ष - गाँधी पक्ष और फारवर्ड ब्लॉक - ब्रिटिश-विरोधी और युद्ध-विरोधी नीति अपना चुके थे इसलिये अब भारत की आजादी प्राप्त करने के लिये और भी बड़ी योजनाओं और कार्यवाहियों के बारे में सोचने का अवसर था।

उस समय मुझे बिना मुकदमा चलाये जेल भेज दिया गया था। काफी समय तक अध्ययन और सोच विचार के उपरांत मुझे तीन बातों के बारे में विश्वास हो गया था - पहला यह कि ब्रिटेन युद्ध में अवश्य हारेगा और ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जायेगा। दूसरे यह कि ब्रिटेन चाहे जितनी बुरी हालत में हो, वह भारत की सत्ता भारतवासियों को कभी नहीं सौंपेगा और भारतवासियों को अपनी आजादी के लिये लड़ना ही पड़ेगा। तीसरे यह कि भारत को तभी आजादी मिल सकती है जबकि वह ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा ले और शक्तियों से मिलकर काम करे जो ब्रिटेन से लड़ रही है। लेखकर ने यही निष्कर्ष निकाला था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश करना चाहिये। अब तक मैं ग्यारह बार अंग्रेजों की जेल में रह चुका था लेकिन मैंने अनुभव किया कि जब इतिहास का निर्माण कहीं और हो रहा हे तो जेल के सीखचों में निष्क्रिय रूप से बंद पड़ रहना बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। अब मैंने कानूनी तौर से बाहर आने की तरकीब सोची, पर ऐसी कोई तरकीब नजर नहीं आई क्योंकि ब्रिटिश सरकार युद्ध के दौरान मुझे जेल में बंद रखने का पूरी तरह निश्चय कर चुकी थी। इस पर मैंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि उसके पास मुझे जेल में रखने का कोई कानूनी और नैतिक औचित्य नहीं है और यदि मुझे नहीं छोड़ा गया तो मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। मैं जिन्दा या मुर्दा जेल से बाहर आने के लिये कृत-संकल्प था।

सरकार ने इस अल्टीमेटम को हंस कर उड़ा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। अंतिम समय में गृहमंत्री ने मेरे भाई शरत चंद्र बोस से, जो प्रांतीय विधान मंडल में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, मुझे यह बताने का अनुरोध किया कि यह मेरा पागलपन है और सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं करेगी। काफी रात गये वह मुझसे मिलने मेरे जेल की कोठरी में आये और मंत्री का संदेश कह सुनाया, और यह भी बताया कि सरकार का रवैया बहुत अमैत्रीपूर्ण था। अगले दिन मैंने जैसी घोषणा की थी उसके अनुसार अपना अनशन आरंभ कर दिया। सात दिन के बाद ही अधिकारियों को काफी डर लगने लगा कि कहीं मैं जेल में ही न मर जाऊँ। जल्दी-जल्दी उच्च अफसरों की एक गुप्त बैठक बुलाई गई जिसमें मुझे इस इरादे से रिहा करने के बारे में निश्चय किया गया कि एकाध महीने में स्वास्थ्य ठीक होते ही मुझे फिर गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

रिहा होने के बाद मैं करीब 40 दिन अपने कमें में ही बंद रहा और जरा भी देर के लिये बाहर नहीं निकला। इस अवधि में मैं युद्ध की सारी स्थिति का जायजा लेता रहा और इस निर्णय पर पहुँचा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को विदेशों में क्या हो रहा है, इस बात की पूरी-पूरी और आंखों देखी स्थिति मालूम होनी चाहिये और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को तोड़ने में अपना योगदान करना चाहिये। यह कैसे संभव हो, इस बारे में काफी सोच-विचार करने के बाद मेरे सामने बसे एक यही चारा था कि मैं खुद विदेश जाऊँ। जनवरी 1941 के अंत में एक दिन काफी रात में चुपके से अपने घर से निकल पड़ा यद्यपि गुप्तचर पुलिस हमेशा मेरे पीछे लगी रहती थी पर मैं किसी न किसी प्रकार उसे झांसा देने में सफल हो गया और काफी लम्बे और साहसिक सफर के बाद भारत की सीमा को पार करने में सफल हो गया। मेरे इस प्रकार भाग निकलने जैसी सनसनीखेज घटना देश में बहुत समय से नहीं हुई थी।

1941 को सारे साल सविनच अवज्ञा आंदोलन चलता रहा, लेकिन इसमें गाँधी और उनके अनुयायियों ने कोई जोश नहीं दिखाया। महात्माजी ने अनुमान किया कि इस प्रकार नरम नीति पर चलने से आखिरकार समझौते का रास्ता खुला ही रहेगा लेकिन इस बारे में निराशा ही उनके हाथ लगी। उनकी अच्छाई को सरकार ने कमजोरी समझा और वह युद्ध की जरूरतों के लिये भारत का शोषण अपनी पूरी क्षमता भर करती रही। सरकार ने भूतपूर्व कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय जेसे एजेंटों का भी खुब लाभ उठाया जो ब्रिटेन के हाथों अपने आपको बेचने को तैयार थे।

अंतत: जब नवंबर 1941 में सुदूर-पूर्व युद्ध के बादल मंडराने लगे तो सरकार की आत्मवंचना भंग हुई। दिसंबर के शुरू में कांग्रेस के गाँधीवाद नेताओं को अचानक रिहा कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही वामपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। उदाहरण के लिये जब सुदूर-पूर्व में लड़ाई छिड़ गयी तो मेरे श्री शरत चंद्र बोस को बिना मुकदमा चलाये जेल भेज दिये गये। संभवत: सरकार ने यह सोचा होगा कि गाँधीवादियों को रिहा करने और वामपंथियों को जेल भेजने की दुहरी नीति से वह कांग्रेस के साथ कोई समझौता कर पायेगी।

ब्रिटिश सरकार की समझौते की इस इच्छा का कांग्रेस के गाँधीवादी पक्ष ने भी समुचित उत्तर दिया। वर्धा में 16 जनवरी, 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके फिर से युद्ध-प्रयत्नों में सहयोग देने का प्रस्ताव किया। थोड़े ही दिन बाद फरवरी 1942 में ब्रिटिश सरकार की पहल पर चीन के मार्शल च्यांग काई शेक कांग्रेस के नेताओं को ब्रिटिश सरकार के साथ कोई समझौता करने को तैयार करने के लिये भारत आये। एक महीने के बाद मार्च 1942 में एक अमेरिकी टेक्नीकल मिशन, कुछ अमेरिकी राजनीतिज्ञ, कुछ पत्रकारों का एक दल और कुछ अमेरिकी सैनिक टुकड़ियां भारत आईं। अप्रैल में भारत स्थित ब्रिटिश कमाण्डर-इन-चीफ को मार्शल च्यांग काई शेक की सहायता लेने और चीनी सेनाओं को बर्मा भिजवाने के लिये मजबूत होना पड़ा।

एक सप्ताह की लड़ाई में ही 15 फरवरी 2942 को सिंगापुर का पतन हो जाने से ब्रिटिश और अमेरिकी में बहुत चिन्ता फैल गयी। जब जापानी सेनाओं ने मलाया की लड़ाई जीतकर बर्मा में बढ़ना शुरू किया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इतिहास का एक नया पन्ना पलटने को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने 11 मार्च 1942 को एक तुष्टिकरण वक्तव्य दिया कि युद्धकालीन मंत्रिमंडल की ओर से सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने की घोषणा की।

मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स बड़ी शुभ घड़ी में भारत आये। जापानी सेनायें जिस तरह जीत पर जीत पाती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी उसको देखकर ब्रिटिश सरकार ढीली पड़ गयी थी और क्रिप्स के बारे मे आम जनता की राय थी कि उस समय वही उस काम के लिये सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे जो उन्हें सौंपा गया था। लेकिन उनके प्रयत्न भी असफल रहे क्योंकि वह जो कुछ अपने साथ लेकर आये थे वह था युद्ध समाप्ति बाद औपनिवेशवाद दर्जे (डोमिनियम स्टेट्स) का वायदा। उसी के साथ यह धमकी थी कि लड़ाई खत्म होने के बाद शायद भारत का विभाजन भी कर दिया जाये। 10 अप्रैल को कांग्रेस कार्यसमिति ने इस आधार पर क्रिप्स प्रस्तावों को ठुकरा दिया कि इनसे भारत की स्वाधीनता की मांग किसी तरह पूरी नहीं होती। 11 अप्रैल को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारतवासियों के नाम अपना विदाई संदेश प्रसारित किया और निराश होकर स्वदेश लौट आये।

क्रिप्स के भारत चले के बाद 27 अप्रैल को कांग्रेस कार्यसमिति की इलाहाबाद में बैठक शुरू और कई दिनों तक चली। 1 मई को एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें क्रिप्स प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया था और यदि कोई विदेशी सेना भारत में दाखिल होती है तो उसका अहिंसा और असहयोग द्वारा सामना करने का निश्चय किया गया था। क्योंकि ब्रिटेन के साथ कोई समझौता नहीं हो सका था इसलिये उसकी तरफ से जापानी या किसी दूसरी सेना के विरुद्ध सक्रिय रूप से लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था।

गाजा में मानवीय सहायता तुरन्त पहुँचायी जाये।

गाजा में 15 लाख फिलिस्तिनियों पर इजरायल का वहशी सैन्य हमला नरसंहार है। कोई 1300 से जयादा फिलिस्तिनी - जिनमें सैकड़ों महिलायें और बच्चे भी शामिल है - मारे गये है और करीब 5000 घायल हुये है। कोई 26,000 से ज्यादा घर तबाह हो गये हैं और स्कूलों, अस्पतालों तथा बुनियादी ढाँचे पर लक्ष्यवद्ध बमबारी की गयी है आज फिलिस्तिनियों के पास न बिजली है, न पीने का पानी, न दवायें हैं और न ही खाना। अस्पताल घायलों का उपचार तक नहीं कर पा रहे क्योंकि न सिर्फ दवाओं की बल्कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है।

इजरायली सेना चली गयी है, पर घेराबन्दी अभी भी जारी है। इजरायलियों का हुक्म चल रहा है और फिलिस्तिनियों के लिये भोजन तथा दवाओं की आपूर्ति को रोक रहे हैं। गाजा पर इजरायल के बार-बार होते हमलों और फिलिस्तिनी जमीन पर उसका कब्जा जारी रहने के लिये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जवाबदेह हैं। भारत सरकार, फिलिस्तीननी ध्येय के लिये सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रही है, जबकि वह इजरायली हथियारों का सबसे खरीददार है और इजरायली सैन्य बलों को सब्सीडाइज करने में मदद कर रही है।

इस नरसंहार के प्रमि हम खामोश दर्शक बने नहीं रह सकते और फिलिस्तिनी जनता के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करने के लिये एक साथ आने की जरूरत है और इजरायल के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी तथा भारत सरकार द्वारा दबाव बनाने की जरूरत है। मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि भारती अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर शायद ही गाजा पर हमले की कोई खबर आयी हो। कुछेक दिनों को छोड़कर अधिकतर राष्ट्रीय अखबारों ने वहां मौत तथा विनाशलीला की खबर कभी अपने मुखपृष्ठों पर नहीं छापी।

गाजा में मानवीय संकट से आगे जाकर यह सम्मेलन अपने पूरे क्षेत्र पर अपना स्वतंत्र देश बनाने और इजरयल तथा उसके पश्चिमी आकाओं की साजिशों से उबरकर विकास का अपना रास्ता चुनने, जो कि उसका अधिकार है, के लिये फिलिस्तिनी जनता के संघर्ष के साथ अपनी दृढ़ एकजुटता का इजहार करती है।

यह सम्मेलन भारत सरकार से मांग करती है कि-

1. अपनी इजरायल परस्त विदेश तथा सुरक्षा नीतियों को बदले।
2. इजरायल के साथ सैन्य संधियों को खत्म करें।
3. इजरायली एयरक्राफ्ट उद्योगों के साथ हुये 10,000 करोड़ रुपये के मिसाइल सौदे को समाप्त करें।
4. गैर कानूनी इजरायली बस्तियों से आने वाले तमाम मालों का बहिष्कार करे और
5. दूसरे गुटनिरपेक्ष देशों के साथ मिलकर फिलिस्तिन पर एक पहलकदमी करें।

फारवर्ड ब्लॉक उत्तर प्रदेश राज्य कमिटी की बैठक

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की उत्तर प्रदेश कमिटी की बैठक पीलीभीत में 8 फरवरी 2009 को हुयी। बैठक की अध्यक्षता साथी हंसराज अकेला ने की। केन्द्रीय कमिटी की 10 एवं 11 जनवरी 2009 की बैठक के आलोक में राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। राज्य कमिटी आगामी 15 मार्च 2009 को कन्नौज जिला के गुरसहाय गंज बैठक में लोकसभा चुनाव के संबंध निर्णय करेगी।

कामगारों का विशाल संसद मार्च

50 हजार कामगारों का विशाल समूह नारे लगाता हुआ रामलीला मैदान से जंतर-मंतर की ओर साथी एस.पी. तिवारी (टी.यू. सी.सी.), साथी गुरूदास दासगुप्ता (सांसद-एआईटीयूसी), साथी तपन सेन (सांसद - सीआईटीयू), साथी शंकर साहा (एआईयूटीयूसी), साथी एम. वेंकटचलन (एबाईबीइएफ) आदि अनेक नेताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ा। रैली विशाल जनसभा में बदल गयी जिसमें अध्यक्षय भाषण साथी डी.एन. झा (टी.यू.सी.सी.) दिल्ली राज्य समिति के साथ साथी अमरजीत कौर (एआईटीयूसी) साथी स्वदेश राय (सीआईटीयू), साथी कृष्णा चक्रवर्ती (एआईटीयूसी) और साथी आर.एन. ठाकुर (एआईसीसीटीयू) ने संबोधित किया। सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के नेतागण साथी डी.एल. सचदेव (एआईटीयूसी), साथी सपन मुखर्जी (एआईसीसीटीयू) साथी सुकुमार सेन (ऑल इण्डिया स्टेट गवर्नमेन्ट इम्प्लाईज फेडरेशन) मख्य वक्ता थे।

साथी एस.पी. तिवारी, महासचिव टीयूसीसी ने अपने ज्वलंत भाषण में न्यू इण्डस्ट्रियल एण्ड इकोनॉमिकल रिजिम (1986) वाशिंगटन समझौता को विस्तृत उद्घृत किया जिसे 1991 में हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने लागू किया जिससे पूँजीवादियों को बढ़ावा मिला तथा साथ ही विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लूट मचाने की छूट मिली और हमारी मिश्रित व्यवस्था ध्वस्त हुई और तथाकथित विश्वसनीय देश के सरकारी उपक्रम लड़खड़ा गये। वित्त और श्रम क्षेत्र में सुधार के नाम पर विदेशी कंपनियों की दखल बढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाले पारंपरिक छोटे लघु उद्योगों को इन्होंने निगल लिया। इन लघु-उद्योगों का देश के जीडीपी में भी बड़ा भाग रहा करता था। अनियोजित सेक्टरों के अंतर का फायदा उठाते हुये देश के बड़े कारपोरेट घरानों ने अपने सहयोगी पूँजीपतियों के साथ नियोजित सैक्टरों के भी बड़े भाग को निगल लिया और मेहनतकश जनता का जीवन दूभर कर डाला।

उन्होंने सभी स्तरों पर मेहनतकश जनता की एकता पर बल दिया जिससे पूँजीवादियों और इनकी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकने में जारी संघर्ष को तेज किया जा सके और समाजवादी सरकार देश की मेहनतकश जनता के नेतृत्व में बनाई जा सके।

सभा के समापन के बाद 9 सदस्यीय दस्ता कार्यकारी प्रधानमंत्री प्रणव मुखर्जी से मिला जिन्होंने देश ट्रेड यूनियनों के 13 सूत्रीय माँग पर विचार करने का आश्वासन दिया।

किसान बचाओ, देश बचाओ रैली

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की महाराष्ट्र राज्य कमिटी की बैठक नागपुर में 11 फरवरी 2009 को साथी धर्मराज दूबे ने बैठक की अध्यक्षता में संपन्न हुयी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साथी देवब्रत बिश्वास भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में पाटी की आगामी महासम्मेलन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कि लिये एक 4 सदस्यीय संयोजन समिति का गठन किया गया। जिसके संयोजक साथी धर्मराज दूबे निर्वाचित किये गये। इसके अलावा साथी अरूण वांकर, साथी अलवन्त राय मेहता और साथी देवीदास भोरे इस कमिटी के सदस्य निवार्चित किये गये। इसके अलावा यही कमिटी सदस्यता सूची की जाँच करेगी तथा लोकसभा चुनाव हेतु संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी। राज्य कार्यालय नागपुर में स्थापित किया जायेगा तथा वर्ग संगठनों के कार्यों की जिम्मेदारी के लिये विशेष उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा। जिसमें वर्ग संगठनों के लिये सहयोगी होंगे - टी.यू.सी.सी. - साथी बबन भोरे, सुखदेव ढेकले; किसान सभा - साथी मेघधाम टाड़े; यूथ लीग - साथी रामेश्वर चौंदा और राज सलोटे होंगे। अग्रगामी किसान सभा 15 मार्च 2009 को योतमल में किसान रैली का आयोजन करेगा, जिसका नारा होगा किसान बचाओ, देश बचाओ।